मंडल आयोग के प्रतिवेदन का कार्यान्वयन

711. **श्री मोहम्मद अफजल** उर्फ **मीम अफजल** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडल आयोग के प्रतिवेदन के कार्यान्वयन के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद इस संबंध में सरकार द्वारा 30 जून, 1994 तक क्या कार्य-वाही की गई है ;

(ख) सरकार द्वारा मंडल आयोग के प्रतिवेदन को पूर्ण रूप से कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस प्रतिवेदन को अब तक कितने राज्यों में लागू किया जा चुका है।

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.के. तंगकाबालू) : (क) केन्द्र सरकार ने इंदिरा साहनी व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (मंडल मामला) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

(1) केन्द्र सरकार के सिविल पदों और सेवाओं में "सम्पन्न वर्ग" के निष्कासन की शर्त पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों में 27% आरक्षण का प्रावधान करते हुए 8 सितम्बर, 1993 को आदेश जारी किया।

(2) केन्द्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से 14 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हि० प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियां अधिसूचित कीं।

(3) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कार्यान्वित करने हेतु केन्द्र सरकार में सम्बद्ध प्राधिकारियों को समुचित अनुदेश जारी किए।

(4) केन्द्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्राप्त करने के प्रयोजन से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु राज्य सरकारों के सबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी किए।

(5) दिनांक 20-2-1994 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार की प्रथम नियुक्ति की।

(ख) मंडल आयोग की पूर्ण रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) इस संबंध में ब्यौरे राज्य सरकारों से एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जायेंगे।

Reservation for OBCs in Educational Institutions

712. SHRI JALALUDIN ANSARI : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to extend 27 percent reservation to those belonged to OBCs in educational institutions; and

(b) if so, the details threof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU) : (a) and b) The matter is under examination of the Government.

Reservation system in Southern States

713. SHRI N. GIRI PRASAD: Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in some of the Soutern States where reservation system has been prevailing even before the implementation of Mandal Commission re-